मानवाधिकार की अवधारणा का विकास वृहत् प्रमाण से वैसे अवधारणा का विकास सत्ता के निरंकुश प्रयोग पर अंकुश लगाना है। ब्रिटेन में ~~गौरवपूर्ण~~ क्रांति (1689) ने मानवाधिकार की अवधारणा को विस्तार दिया। फ्रांसीसी क्रांति के बिल ऑफ राइट्स के द्वारा व्यक्ति को उन मौलिक स्वतंत्रताओं को मान्यता दी गई जिनका। अब तक हनन किया जाता रहा था।

वर्तमान मानवाधिकार संबंधी गतिविधियाँ वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम हैं। ~~द्वितीय विश्व यु~~ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित अमानवीय घटनाओं की भर्त्सना करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट (1882-1945) का भाषण (1940) जिसमें रूजवेल्ट ने मनुष्य की चार मूलभूत स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया था, भविष्य में मानवाधिकार संबंधी घोषणा का मुख्य आधार बना। फ्रैंकलिन की पत्नी एलेनोर रूजवेल्ट (1884-1962) की अध्यक्षता में 1946 में गठित मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत और घोषित किए जाने के साथ ही विश्व समुदाय द्वारा इसे न केवल मान्यता दी गई बल्कि अपने-अपने संविधानों में स्थान देकर विविध स्वरूपों में प्रदान किया गया। 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई। यह एक संयोग है कि इसी समय हमारे भारतीय संविधान का प्रणयन हो रहा था।

Scanned with OKEN Scanner

Mr. Vinita Bharadwaj

THURSDAY • MARCH

MARCH 2016

10

WEEK 10 Sunrise : 06:09 am • Sunset : 05:51 pm

3-2-2022

Human rights Problems and Prospects

हमारे देश में प्रत्येक युग में मानवाधिकार के महत्व को स्वीकार किया गया है। महात्मा बुद्ध ने "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" का संदेश दिया था। सूर, कबीर, तुलसी, रैदास आदि ने भी अपनी रचनाओं में मानव अधिकारों के महत्व को सामने रखा। डॉ० भीमराव अंबेडकर ने 20वीं सदी में मानवाधिकारों के लिए अपने संघर्ष किया। डॉ० अम्बेडकर ने समाज के निम्न वर्ग के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अधिकारों को मानव अधिकारों से जोड़ा। यह आश्चर्य का विषय है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी शोषण, अन्याय, छुआछूत, स्त्री-पुरुष असमानता का अस्तित्व बना हुआ है; जिसके कारण मानव अधिकारों का हनन आज भी किया जा रहा है।

वर्तमान युग में संभावित रूप में भारत में नागरिक अधिकार आंदोलन की ~~शुरुआत~~ शुरुआत 1936 में 'सिविल लिबर्टीज यूनियन' के गठन से हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणा-पत्र पर भारत ने 1948 में हस्ताक्षर किए थे ~~क्योंकि समाज~~

★ मानवाधिकार की समस्याएं → हाल ही में देश में 10 दिसम्बर 2018 को 70वीं मानवाधिकार सालगिरह मनाई गई।

★ 1948 में 48 देशों के समूह ने समूची मानव जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए।

★ 1993 में NHRC अर्थात् राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया।

आज देश में जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है वैसे में मानवाधिकार और उनसे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है।

2016

They are able because they think they are able.

Scanned with OKEN Scanner

डेली The हिन्दू

देश भर मावलिंचिन की घटनाएँ, बिहार में मुजफ्फरपुर की घटनाएँ, और उसके बाद उत्तरप्रदेश के देवरिया में शेल्टर होम में ~~बच्चियों~~ बच्चियों के साथ हुए विनत्सकृत देश में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं।

कई विवादास्पद घटनाएँ; मसलन ऑपरेशन "ब्लू स्टार" के बाद उत्पन्न दंगों, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देशभर में हुए फसाद, गुजरात में हुए हिंदू-मुस्लिम दंगों, ~~इत्यादि। समय की~~ कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगों इत्यादि के बाद तो देश में मानवाधिकार का हनन देश भर में दिया नहीं है।

चर्चा में क्यों है?

☆ हालांकि हमें ऐसे कई मामले देखने को मिल जाते हैं जब मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए NHRC अपने कर्तव्यों का ~~बख~~ बखूबी पालन करता है लेकिन फिर भी NHRC अन्य कई मामलों पर अपनी अनुसंशाएँ देने पर लाचार रहता है।

☆ मानवाधिकार का मतलब और यह मौलिक अधिकार से किस अर्थ में जुड़ा है यह समझ लेना होगा बेहतर।

~~तो क्या हम विश्वाली व्यवस्था मान ली जाए~~

मानवाधिकार क्या है? ~~इसके ...~~ →

☆ मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है।

☆ इसमें शामिल हैं जिन्दगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार।

Scanned with OKEN Scanner

संवेदना

★ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया मानवाधिकार संबंधी घोषणापत्र : मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से इतर होते हैं।

★ मौलिक अधिकार देश के संविधान में अभिलिखित अधिकार : ये अधिकार देश के नागरिकों को और किन्हीं परिस्थितियों में देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होती है।

★ मौलिक अधिकार के कुछ तत्व मानवाधिकार के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे : जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार :

★ भारत के द्वारा मानवाधिकार के लिए उठाए गए कदम - "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग"

भारत में मानवाधिकारों की रक्षा करने की दिशा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश की सर्वोच्च संस्था।

★ मानवाधिकारों का लोकपाल

★ उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसके अध्यक्ष हैं।

★ राष्ट्रीय मानवाधिकारों के वैश्विक गठबंधन का हिस्सा तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पैसिफिक फोरम का संस्थापक सदस्य भी है NHRC

★ NHRC को मानवाधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार भी है।

Scanned with OKEN Scanner